Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 अगस्त, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-18-august-2020

सत्यपाल मलिक

गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 18 अगस्त, 2020 से मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके स्थानांतरण के बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। मलिक ने वर्ष 2018-19 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। सत्यपाल मलिक ने वर्ष 2017-18 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 में उन्हें ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिये अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पूर्व मलिक को वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्हें वर्ष 1980-86 के दौरान राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया। भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है।** राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को **नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements-ARIIA) 2020** जारी की गई है। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष दस संस्थानों की घोषणा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। रैंकिंग के प्रमुख संकेतकों में संस्थान के प्रशासन में नवाचार, नवीन शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण, उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। यह प्रयोग उस समय किया गया जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का अनावरण किया।

विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर, 2020 को पहली बार **विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन** आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिये दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा में विश्व सौर बैंक का विचार प्रस्तुत किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों में इस

बैंक का आकर 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर होगा। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-21 के दौरान की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान में स्थित है।

CAMPA फंड

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 18 अगस्त, 2020 को 24 राज्यों के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ने घोषणा की कि CAMPA फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिये किया जाएगा। इसके साथ ही, वन-आधारित विचलन निधि को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा। इस बैठक के दौरान वृक्षारोपण पहल, नगर वन योजना के तहत शहरी वानिकी को बढ़ावा देना, 13 प्रमुख नदियों का उपचार, पतित वन क्षेत्रों का LIDAR आधारित सर्वेक्षण, वन उपज के आवागमन की सुविधा के लिये राष्ट्रीय पारगमन पोर्टल पर विमर्श किया गया है। राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।